

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केस्पटी-भद्रीगाड़ एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत-

- 1— एन0एच0-507 — यमुना पुल-खरसोन क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 किमी0
- 2— यमुना पुल-मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
- 3— यमुना पुल-सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
- 4— एस0एच0-08— मसूरी-चम्बा मार्ग, मसूरी-धनोल्टी, 34 किमी0 ✓

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राम पंचायत का नाम.....धनोल्टी  
तहसील.....धनोल्टी जिला.....टिहरी गढ़वाल

—:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::—

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जीओ (अॉप्टिकल फाइबर लैन) परियोजना के निर्माण हेतु (0.05-के-माझे हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.190 हैक्टेयर, सिविल सोयल भूमि 0.110 हैक्टेयर, वन पांचात भूमि 2.00 हैक्टेयर) अर्थात् कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का...जीओ रिलाइंस इंफोकॉम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनोल्टी द्वारा दिनांक 7/11/2019 को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरत्त चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।\* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...  
धनोल्टी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.350 हैक्टेयर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के, मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी-भद्रीगढ़ एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत-

- 1- एन0एच0-507 - यमुना पुल-खरसोन कथारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 किमी0
- 2- यमुना पुल-मसूरी बैण्ड, जीरो प्लाइंट 21 किमी0
- 3- यमुना पुल-सुमन कथारी, 11.2 किमी0
- 4- एस0एच0-08- मसूरी-चम्बा मार्ग, मसूरी-धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉर्म लिं0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राम पंचायत का नाम सिंगा कैप्टन  
तहसील धनोल्टी जिला प्रतापगढ़

-:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::-

उत्तराखण्ड में जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रिलाइंस टिहरी परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 हेक्टेयर) हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पांचायत भूमि 0 हैक्टेयर) अर्थात् कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस टिहरी ग्राम पंचायत/विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के दिश्य में ग्राम पंचायत सिंगा कैप्टन द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्भत करने हेतु विरतुत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।\* उपरित्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ..... प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के नसूरी वन प्रभाग, केम्पटी-भद्रीगाड़ एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत-

- 1- एन0एच0-507 - यमुना पुल-खरसोन कथारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 किमी।
- 2- यमुना पुल-मसूरी बैण्ड, जीरो प्लाइंट 21 किमी।
- 3- यमुना पुल-सुमन द्वयारी, 11.2 किमी।
- 4- एस0एच0-08- मसूरी-चम्बा मार्ग, मसूरी-धनोल्टी, 34 किमी।

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी। और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लिंग, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेवालखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राम पंचायत का नाम रावरसन  
तहसील कामोद जिला राजस्थान

-:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

उत्तराखण्ड में जनपद रावरसन के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि. परियोजना के निर्माण हेतु (0.05ग्राम परियोजना हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोलाल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि शूद्ध हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रावरसन द्वारा दिसंक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।\* उपरित्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



₹ 50/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी-भद्रीगाड एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत—

- 1— एन0एच0—507 — यमुना पुल-खरसोन क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 किमी0
- 2— यमुना पुल-मसूरी बैण्ड, जीरो प्लाइंट 21 किमी0
- 3— यमुना पुल-सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
- 4— एस0एच0—08— मसूरी-चम्बा मार्ग, मसूरी-धनोली, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लिं0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेवालखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भट्टोली  
तहसील दिल्ली जिला मुरादाबाद

—:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::—

उत्तराखण्ड में जनपद दिल्ली के अन्तर्गत रिलाइंस कॉम्पोनेंट्स लिमिटेड परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 नए हैक्टेयर आक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर वन पांचायत भूमि 0.36 कि. हैक्टेयर) अर्थात् कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस कॉम्पोनेंट्स लिमिटेड वन भूमि/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भट्टोली द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।\* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चाचा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ..... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केमटी-भद्रीगाड़ एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत-

- 1- एन0एच0-507 - यमुना पुल-खरसोन कयारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 किमी0
- 2- यमुना पुल-मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
- 3- यमुना पुल-सुमन कयारी, 11.2 किमी0
- 4- एस0एच0-08- मसूरी-चम्बा मार्ग, मसूरी-धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेयर, में सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉर्म लि�0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राम पंचायत का नाम टिहरी  
तहसील टिहरी जिला उत्तराखण्ड

-:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::-

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकॉर्म लि0. परियोजना के निर्माण हेतु (०.०५ हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि ०.१९ हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि ०.११ हैक्टेयर, वन पांयत भूमि ०.२६ हैक्टेयर) अर्थात कुल ०.३५० हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकॉर्म विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टिहरी द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।\* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित